भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 511

उत्तर देने की तारीख-04/02/2026

सरकारी विद्यालयों की कक्षाओं का डिजिटलीकरण किया जाना

511 **श्री संदोष कुमार पी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में डिजिटलीकृत कक्षाओं वाले सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की संख्या की राज्य-वार सूची क्या है;

(ख) देश भर में सरकारी विद्यालयों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के एकीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या पहल की गई हैं;

(ग) पिछले पाँच वर्षों के दौरान देश भर में सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के एकीकरण के लिए कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के एकीकरण हेतु संवितरित राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना समग्र शिक्षा लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में लागू किया जाता है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत छठी से बारहवीं कक्षा वाले सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

प्रबंध पोर्टल के अनुसार, अब तक, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को 1,79,153 आईसीटी प्रयोगशालाएं और 1,76,738 स्मार्ट क्लासरूम संस्वीकृत किए गए हैं। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अनुमोदित आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ख): दिनांक 17 मई, 2020 को 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के भाग के रूप में पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तत्वावधान में देश भर में शिक्षा के लिए मल्टी-मोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) मातृभाषा/स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पहलों की प्रभावकारिता का उपयोग, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एनसीईआरटी के साथ सहयोग करते हैं। पीएम ई-विद्या में भारत सरकार में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों (एबी)/अन्य मंत्रालयों को आवंटित 200 डीटीएच टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनल शामिल हैं ताकि वे कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में अपनी आवश्यकता के अनुसार पूरक शिक्षा प्रदान कर सकें।

ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (दीक्षा) सभी ग्रेड के लिए क्यूआर कोडेड एनर्जेइज्ड पाठ्यपुस्तकों (ईटीबी) के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों सहित स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए देश का एक राष्ट्र, एक डिजिटल मंच है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/एबी ने बहुभाषावाद को सक्षम करने वाली मातृ स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में 3.7 लाख से अधिक सामग्री तैयार की है और योगदान दिया है। दीक्षा ऑफलाइन सीमित अथवा बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करता है। हितधारकों के पास दीक्षा पर 450+ से अधिक वर्चुअल लैब और 100 वर्चुअल स्किल लैब (हिंदी और अंग्रेजी में 50-50) तक पहुंच है।

यूडाइज+ 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, 5,93,615 सरकारी स्कूल इंटरनेट कनेक्शन से सुसज्जित हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने बजट 2025-26 में बीएसएनएल द्वारा दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 'भारतनेट' परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रावधान की घोषणा की है।

(ग) और (घ): सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट क्लासरूम के लिए पिछले पांच वर्षों (अर्थात 2020-21 से 2024-25 तक) में आवंटित निष्क्रिय और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्रमशः **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

"सरकारी विद्यालयों की कक्षाओं का डिजिटलीकरण किया जाना" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री संदोष कुमार पी द्वारा दिनांक 04 फरवरी, 2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 511 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अनुमोदित आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित आईसीटी लैब्स	अनुमोदित स्मार्ट क्लासरूम
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	162	49
2	आंध्र प्रदेश	9671	6840
3	अरुणाचल प्रदेश	794	345
4	असम	8400	7146
5	बिहार	4942	11586
6	चंडीगढ़	155	186
7	छत्तीसगढ	6965	10771
8	दमन और दीव- दादरा और हवेली	153	192
9	दिल्ली	2208	5696
10	गोवा	463	87
11	गुजरात	6179	7155
12	हरियाणा	5446	3556
13	हिमाचल प्रदेश	3893	2858
14	जम्मू और कश्मीर	4341	4428
15	झारखंड	5447	2459
16	कर्नाटक	9536	4099
17	केरल	2489	752
18	लद्दाख	200	165
19	लक्षद्वीप	28	0
20	मध्य प्रदेश	8489	12573
21	महाराष्ट्र	11387	6006
22	मणिपुर	997	565
23	मेघालय	545	25
24	मिजोरम	1166	244
25	नागालैंड	811	712
26	ओडिशा	10084	11776
27	पुदुचेरी	258	152
28	पंजाब	8965	3938
29	राजस्थान	13408	16891
30	सिक्किम	385	301
31	तमिलनाडु	16595	9832
32	तेलंगाना	7419	6248
33	त्रिपुरा	1782	1162
34	उत्तर प्रदेश	20098	34533
35	उत्तराखंड	1108	2829
36	पश्चिम बंगाल	4184	581
	कुल	**1,79,153**	**1,76,738**

स्रोत: प्रबंध पोर्टल (21.01.2026 की स्थिति के अनुसार)

अनुलग्नक -II

"सरकारी विद्यालयों की कक्षाओं का डिजिटलीकरण किया जाना" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री संदोष कुमार पी द्वारा दिनांक 04 फरवरी, 2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 511 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाओं के लिए पिछले पांच वर्षों (अर्थात वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक) में आवंटित निधियां और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा**

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईसीटी लैब्स और स्मार्ट क्लासरूम	
		आवंटित निधि	उपयोग की गई निधि*
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	145.7	664.8
2	आंध्र प्रदेश	30334.4	38039.2
3	अरुणाचल प्रदेश	1688.6	1070.0
4	असम	35790.7	28612.2
5	बिहार	14994.7	35937.8
6	चंडीगढ़	574.9	204.8
7	छत्तीसगढ	32774.5	6958.2
8	दमन और दीव- दादरा और हवेली	1064.3	788.3
9	दिल्ली	3895.1	2148.0
10	गोवा	13.4	6.6
11	गुजरात	20707.6	15949.8
12	हरियाणा	11968.6	10975.9
13	हिमाचल प्रदेश	11720.3	7530.3
14	जम्मू और कश्मीर	13698.9	6288.3
15	झारखंड	24908.7	15070.9
16	कर्नाटक	12158.8	6892.6
17	केरल	1227.3	612.0
18	लद्दाख	862.7	657.0
19	मध्य प्रदेश	31852.9	4915.9
20	महाराष्ट्र	12136.9	11349.2
21	मणिपुर	2681.3	4031.8
22	मेघालय	1637.7	1602.8
23	मिजोरम	2519.4	2071.3
24	नागालैंड	2428.8	1360.6
25	ओडिशा	20159.6	21662.3
26	पुदुचेरी	450.4	520.3
27	पंजाब	19793.1	6680.7
28	राजस्थान	36101.9	11302.6
29	सिक्किम	1421.5	1143.8
30	तमिलनाडु	62936.1	27045.6
31	तेलंगाना	15538.4	22404.3
32	त्रिपुरा	6582.8	7353.5
33	उत्तर प्रदेश	93071.8	49310.1
34	उत्तराखंड	10575.8	0.0
35	पश्चिम बंगाल	10695.2	0.0
	कुल	**549112.8**	**351161.4**

स्रोत: प्रबंध पोर्टल (22.01.2026 की स्थिति के अनुसार)

*इसमें राज्य का हिस्सा और गत वर्ष की अव्ययित राशि शामिल है।

**आवंटित और उपयोग की गई निधियां प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है।